भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2835

उत्तर देने की तारीख-07/08/2023

स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम

2835. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

श्री बृजेन्द्र सिंह:

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को किस प्रकार प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया जाएगा;

(ख) ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्वयं पोर्टल पर कितने ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और वर्तमान में कितने छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है;

(ग) स्वयं पोर्टल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह युवाओं/छात्रों के लिए किस प्रकार लाभकारी है;

(घ) क्या सरकार ऑनलाइन माध्यम से मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्रणाली लागू कर रही है और लगभग 1 करोड़ छात्र अन्य योजनाओं के साथ-साथ स्वयं, दीक्षा आदि सहित उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में/वर्ष 2035 तक यूडीसी दिशा-निर्देशों को कम करके उच्च इंटरनेट गति वाले शैक्षिक संस्थानों में डिजिटल बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करके 50% शैक्षिक पाठ्यक्रमों लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और देश में डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कवर करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना के लिए अबतक कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सामाजिक या आर्थिक आधार की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई आईटी पहल की हैं जिनमें स्वयं, दीक्षा, वर्चुअल लैब्स, एफओएसएसईई, समर्थ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भाषा अनुवाद उपकरण आदि शामिल हैं।

उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, "कोई भी, कहीं भी, कभी भी अधिगम" के दृष्टिकोण के साथ शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 9 जुलाई 2017 को स्वयं पोर्टल लॉन्च किया गया था। स्वयं एमओओसी कार्यक्रम के तहत 9 राष्ट्रीय समन्वयकों के

नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न विषयों में शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जिनमें आईआईटी मद्रास, आईआईएम बैंगलोर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) त्रिची शामिल हैं। राष्ट्रीय समन्वयकों को मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में तकनीकी के साथ-साथ बहु-विषयक/अंतर-विषयक पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्वयं पोर्टल (www.swayam.gov.in) के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से पेश किए गए आभासी पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकता है, शिक्षक के साथ बातचीत कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, अकादमिक क्रेडिट अर्जित कर सकता है और उन्हें यूजीसी (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2021 के अनुसार उन्हें अपने अकादमिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकता है।

स्वयं पाठ्यक्रम चार चतुर्थांस दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4 चतुर्थांशों में हैं - (1) वीडियो व्याख्यान, (2) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है (3) परीक्षण और क्विज़ के माध्यम से स्व-मूल्यांकन परीक्षण और (4) शंकाओं के समाधान के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच। छात्र विभिन्न अधिगम की ज़रूरतों जैसे पुनरीक्षण, फ़्लिप्ड क्लासरूम, सहकर्मी सहयोग, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अपस्किलिंग और सतत शिक्षा के लिए भी स्वयम की मदद लेते हैं।

3 अगस्त 2023 तक, कुल 3095 विशेष एमओओसी तैयार किए गए हैं और इसके लॉन्च के बाद से स्वयमपोर्टल पर 10,473 एमओओसी पाठ्यक्रम पेश किए गए हैं। स्वयं एमओओसी में संचयी रूप से 3.59 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं। वर्तमान जुलाई 2023 सत्रके लिए, 1125 पाठ्यक्रमों की पेशकश को मंजूरी दी गई है और अब तक 21.88 लाख नामांकन किए गए हैं।

भारत सरकार ने देश भर के छात्रों को उनके घर पर व्यक्तिगत अधिगम के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए बजट 2022-23 में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है।

पिछले 3 वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के तहत जारी धनराशि नीचे उल्लिखित है:

एनएमईआईसीटी निधि जारी करने का विवरण वित्तीय वर्ष-वार (करोड़ रुपये में)				
वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (31 जुलाई 2023 तक)
जारी निधि	267.71	350.02	395.02	94.21

*****